bjpkamaljyoti@gmail.com संवत 2076 युगाब्द 5120 मूल्य : ₹10 अंक – 14, फरवरी द्वितीय अंक 2021, कुल पृष्ठ – 32

वर्तमान

कमल ज्योति

उत्तर प्रदेश बजट 2021-22

योगी आदित्यनाथ
मा0 मुख्यमंत्री

बजट 2021-22
प्रेस वार्ता
दिनांक : 22 फरवरी, 2021 | स्थान : तिलक हॉल, विधान भवन, लखनऊ

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार

प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय
कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक
नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

@swatantrabjp

योगी सरकार का यह सर्वसमावेशी और बहुआयामी बजट प्रदेश में आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को बढ़ावा देगा एवं गाँव.गरीब.किसान के जीवन विकास में सहायक सिद्ध होगा।

बजट पर विशेष – पेज 18 से

संपादकीय

सांस्कृतिक सरोकारों से विकास की उड़ान

करीब तीन हजार वर्ष पूर्व भारतभूमि पर जिस एकमेव सामाज्य की स्थापना हुई थी उसका श्रेय उस काल के महान राजनीतिज्ञ चाणक्य को जाता है। राजनैतिक चातुर्य के धनी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ में राजा के कर्तव्यों एवं उसके आर्थिक तंत्र के विकास को सर्वसुलभ बनाने का प्रभावी विवरण दिया है।

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें है।

पुनः कौटिल्य कहते हैं कि

तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम् ।
अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः ॥

इसलिए राजा को चाहिए कि वह नित्यप्रति उद्यमशील होकर अर्थोपार्जन तथा शासकीय व्यवहार संपन्न करे। उद्यमशीलता ही अर्थ (संपन्नता) का मूल है एवं उसके विपरीत उद्यमहीनता अर्थहीनता का कारण है।

आज यह बताने का एक प्रमुख कारण है। हमने एक कार्यकर्त्ता और राजनीतिक चिंतन के नाते से देखा है कि सता पर बैठे लोग किस तरह से समाजवादी अर्थप्रणाली का व्यवहार गणित अपनाकर चुनावी वर्ष में अपने वोटों के आधार पर धन का बंटवारा करते हैं। लेकिन...प्रदेश की पांच साल से लोकप्रिय सरकार महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के एजेंडे से बिना डरे किस तरह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक वर्ष के कठिन काल से निकाल कर विकास की ओर ले जाती है, उसका प्रतीक स्वरूप है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट। साढे पांच लाख करोड़ से अधिक का अर्थतंत्र बिना डरे–बिना थके निर्बाध गति से मिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। चुनाव वर्ष में कोई सरकार अगर इतनी चातुर्यता के साथ गांव–किसान–जान जहांन का मंत्र लेकर भारी भरकम परियोजनाओं को पूरा करने का संकल्प दिखा रही हो तो कहना होगा वह एक यशस्वी सरकार है जिसको स्वयं पर भरोसा है और उस सरकार पर आमजन का भरोसा कायम है।

सरकार ने बहुत खूबसूरती के साथ अपने पांचवें बजट से आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के संकल्प का इरादा जताया है। बजट में 'जो कहा सो किया' के संदेश के साथ 'एक बार फिर पांच साल के लिए भाजपा सरकार' का स्पष्ट संदेश है। सरकार पुराने कामों को विस्तार और उन्हें आगे बढ़ाने के साथ नई घोषणाओं के लिए बढी है। धन का प्रावधान किया है और इतने के बाद भी सरकार ने इसे चुनावी बजट बनाने से बचा लिया है। यह ताकत ही भारतीय जनतापार्टी की सरकारों को दूसरों की तुलना में अलग बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार सांस्कृतिक सरोकारों के साथ बहुत सलीके से प्रदेश के सर्वसमावेशी और चहुंमुखी विकास को उड़ान देने की कोशिश के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का इरादा जताते हुए अगली बुनियाद रखने की दिशा में बढ़ी है। लेकिन, यह कवायद इस तरह से हुई कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ– सबका विकास और सबका विश्वास' के संदेश को लेकर कोई सवाल न खड़ा हो, किसी वर्ग में कोई संदेह न खड़ा हो। भाजपा सरकारों की ऐसी नीतियां पार्टी को देश स्तर पर ढृढ़ता प्रदान करती हैं।

इसीलिए गुरुकुल की तर्ज पर जब अपने पांचवें बजट में संस्कृत विद्यालयों का विकास, विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन व आवास की घोषणा हुई तो उसके साथ ही सरकार ने अल्पसंख्यकों और उनके मदरसों के लिए भी धन आवंटन में खुला दिल दिखाया। पूरे देश और प्रदेश को यह भी बताया गया कि, महिलाओं, युवाओं, किसानों, विद्यार्थियों और श्रमिकों के लिए शुरू की जा रही नई और चल रही पुरानी योजनाओं में धन के प्रबंध का लाभ भी तो

संपादकीय

समाज के सभी वर्गों को मिलेगा।

योगी आदत्यनाथ सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के बचे कार्यों को पूरा करने का इरादा जताकर यह प्रतिबद्धता दी है कि, भाजपा आगे भी जो वादे करेगी वह पूरे होंगे। इसके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, प्रवासी मजदूर, कौशल विकास सहित अन्य मुद्दों पर अब तक हुए काम के साथ नई व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कोरोना काल को लेकर विपक्ष को उनके सवालों का चुभता जवाब दिया गया है।

महापुरुषों, शहीदों और अपने पांच वर्ष के कार्यों के द्वारा जहां एक ओर राष्ट्रीय सरोकारों को ऊपर चढ़ाते हुए सभी समीकरणों को दुरुस्त किया वहीं, धार्मिक पर्यटन के साथ रोजगार को जोड़कर प्रदेश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य सहित अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए खुलेमन से धन की व्यवस्था तथा विकास की महत्वाकांक्षी घोषणाओं से भाजपा के एजेंडे पर मजबूती से डटे रहने का इरादा जताकर स्पष्ट किया गया कि हम हवाओं से झुकने वालों में नहीं हैं।

शायद यही वजह रही कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करने वालों से वसूले गए जुर्माने की धनराशि को सदन में बताया। सांस्कृतिक एजेंडे के साथ बजट में हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय खोलने, महाविद्यालयों के भवन बनवाने, प्रतियोगी छात्रों को लैपटॉप देने व कौशल विकास जैसी विधाओं में विश्वविद्यालय खोलने जैसे संकल्प लिए गए।

योगी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए युवाओं, 'मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण' व 'महिला सामर्थ्य' जैसी योजनाओं से 'हर खेत को पानी' और 'आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना' सहित अनेक कामों से किसानों और नई बीमा योजना से मजदूरों को आच्छादित किया है।

महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बजट सराहनीय कहानी कहता दिख रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1200 करोड़ की व्यवस्था है, जबकि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए बजट में सौ करोड़ का प्रावधान है। महिला सामर्थ्य योजना के नाम से जो नई योजना क्रियान्वित की जाएगी, उसके लिए भी 200 करोड़ दिये गये है। पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पोषण अभियान में 415 करोड़ का प्रावधान है। इन सब बजट प्रस्ताव से महिलाओं को स्वास्थ्य सहित विकास में काफी सहायता मिलेगी।

सरकार ने बजट में अपने यानि भाजपा के सियासी समीकरणों को स्पष्ट करने में कोई कोताही नहीं बरती है। 'शहीद चंद्रशेखर आजाद ग्राम सचिवालय' के काम को आगे बढ़ाने, चौरी–चौरा कांड के शताब्दी वर्ष के लिए विशेष बजट का प्रावधान, हर मंडल में सैनिक स्कूल खोलने का संकल्प जताने के साथ आजादी की लड़ाई के वीरों की स्मृति में संग्रहालय बनाने की घोषणा से राष्ट्र के अपने सरोकारों को नई धार दी है। इसके साथ ही ' यूपी गौरव सम्मान' से साहित्यकारों व कलाकारों को जोड़ने और जनजातीय विरासत संजोने के लिए संग्रहालय बनाने के कदम से सर्वसमावेशी सरोकारों का ख्याल रखने का पूरा संदेश देकर बता दिया है कि भाजपा सरकार आम लोगों की सरकार है जो प्रदेश के विकास को समर्पित है।

यह सरोकार उस दौरान और स्पष्ट हो गया जब वाराणसी में 'गोकुल ग्राम' तथा गोवंश की सुरक्षा व संरक्षण पर संकल्प जताते हुए स्वदेशी व राष्ट्र के साथ सांस्कृतिक सरोकारों को छुआ गया। यह सरकार के संदेश को बताने के लिए पर्याप्त है। सरकार की तारीफ इस बात के लिए करनी होगी कि कोराना के संकट से बाहर आकर प्रदेश के बजट में राजकोषीय घाटे को काफी कम रखकर तथा पुराने कामों के साथ नए कामों के लिए धन का प्रावधान कर सरकार ने आर्थिक संरचना को ठोस बनाने का पूरा प्रयास किया है। यह बजट बता रहा है कि योगी सरकार नीतियों व मुद्दों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और उसे इस बजट पर प्रधानमंत्री जी के साथ आम जनता का पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है।

मैं इस अकल्पनीय बजट को लेकर फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो की उस पंक्ति, का उल्लेख कर रहा हूं जो इस पर सटीक उतरती है।

नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हूज टाइम हैज कम

akatri.t@gmail.com

इतिहास लेखकों द्वारा इतिहास निर्माताओं के साथ किए अन्याय को ठीक किया जा रहा है: प्रधानमंत्री

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार 16 फरवरी बसंत पंचमी को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव के स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्‌घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास केवल औपनिवेशिक शक्तियों या औपनिवेशिक मानसिकता वाले लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास ही नहीं है, अपितु भारत के इतिहास को आम लोगों ने अपनी लोककथाओं में भी पोषित किया है और इसे पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताते हुए कहा कि जिन लोगों ने भारत और भारतीयता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें उचित महत्व नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ भारतीय इतिहास लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास निर्माताओं के विरुद्ध की गई अनियमितताओं और अन्याय को अब ठीक किया जा रहा है और इस दिशा में उनके योगदान को स्मरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने लालकिले से लेकर अंडमान निकोबार तक नेताजी सुभाषचंद्, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल और पंच तीर्थ के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को स्मरण करने का उल्लेख किया। उन्होंने

महाराजा सुहेलदेव स्मारक शिलान्यास

कहा कि ऐसे अनेकों व्यक्तित्व हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से मान्यता नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने पूछा कि चौरी–चौरा के बहादुरों के साथ क्या हुआ था, क्या हम इसे भूल सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयता की रक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव के योगदान की भी अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव की पाठ्यपुस्तकों में अनदेखी के बावजूद उन्हें अवध, तराई और पूर्वांचल के लोकगीतों ने लोगों के दिलों में जीवित रखा है। प्रधानमंत्री ने एक संवेदनशील और विकासोन्मुख शासक के रूप में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि महाराजा सुहेलदेव के लिए यह स्मारकआने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ, इस आकांक्षी जिले और आस–पास के क्षेत्रों में लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने दो वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था।

श्री मोदी ने बसंत पंचमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि इस बसंत ने भारत के लिए महामारी की निराशा को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कामना की है कि मां सरस्वती भारत और हर उस देशवासी के ज्ञान और विज्ञान को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जो अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में निर्मित इतिहास, आस्था और आध्यात्मिकता से संबंधित स्मारकों का सबसे बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन और तीर्थयात्रा दोनों क्षेत्रों में भी समृद्ध है और प्रदेश में इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों पर रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं और अब उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से पर्यटकों की अधिकतम संख्या को आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कहा की कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ–साथ आधुनिक कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या हवाई अड्डा और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भविष्य में घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह के पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। उत्तर प्रदेश में एक दर्जन छोटे और बड़े हवाई अड्डों पर काम चल रहा है, जिनमें से कई पूर्वांचल में ही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जैसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें पूरे उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही हैं और यह एक तरह से आधुनिक उत्तर प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का शुभारंभ है। उत्तर प्रदेश दो बड़े समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण ने निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए उत्साहित किया है। इससे उद्योगों के साथ–साथ युवाओं के लिए भी बेहतर अवसर पैदा हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम केप्रति अपनाई गई रणनीति की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने घर लौटे श्रमिकों को रोजगार

देने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा किपिछले 3–4 वर्षों में राज्य नेकोरोना को खत्म करने की दिशा में बड़ा योगदान दिया है। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण पूर्वांचल में मेनिन्जाइटिस की समस्या काफी हद तक कम हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से बढ़कर 24 हो गई है। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का काम चल रहा है। इनके अलावा, 22 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी पूर्वांचल को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन यानी हर घर में पानी पहुंचाना भी प्रशंसनीय कार्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल के घर पहुंचने पर कई तरह की बीमारियों को कम किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, गाँव, गरीब और किसान बेहतर बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा किप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे धनराशि जमा कर दी गई है। ये किसान कभी खाद की एक बोरी खरीदने के लिए भी दूसरों से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करने के लिए रात भर जागना पड़ता था और अब उनकी सरकार ने बिजली की आपूर्ति में सुधार करके ऐसी समस्याओं को दूर किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन कृषि भूमि को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह यह प्रति किसान के स्तर पर कम होती कृषि भूमि के मुद्दे का समाधान करता है। उन्होंने कहा कि जब 1–2 बीघा वाले 500 किसान परिवार संगठित होंगे तो वे 500–1000 बीघा किसानों से अधिक शक्तिशाली होंगे। इसी तरह, सब्जी, फल, दूध, मछली और ऐसे कई व्यवसायों से जुड़े छोटे किसान अब किसान रेल के माध्यम से बड़े बाजारों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू किए गए नए कृषि सुधारों से छोटे और सीमांत किसानों को भी फायदा होगा और इन कृषि कानूनों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देश भर से मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाए हैं, वे अब किसानों को भारतीय कंपनियों से डरा रहे हैं। उनके झूठ और दुष्प्रचार उजागर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानूनों के लागू होने के बाद, उत्तर प्रदेश में धान खरीद पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई। योगी सरकार पहले ही गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। किसानों को भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को सक्षम बनाने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपये भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखेगी कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया जाए।

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार गांव और किसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से किसी भी ग्रामीण के घर पर अवैध कब्जे की संभावना से छुटकारा मिलेगा। इस योजना के तहत, इन दिनों उत्तर प्रदेश में लगभग 50 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। लगभग 12 हजार गांवों में ड्रोन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और अब तक 2 लाख से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड मिल चुके हैं और ये परिवार अब सभी प्रकार की आशंकाओं से मुक्त हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी किसान की भूमि को कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से हड़पा नहीं जा सकता है, इस बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से आम लोगों को भरमाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना है, हमारी प्रतिज्ञा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और हम इस कार्य के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री ने गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की एक चौपाई से अपने संबोधन का समापन किया, ऋतु बसंत बह त्रिबिध बयारी। यानि, बसंत ऋतु में शीतल, मंद सुगंध, ऐसी तीन प्रकार की हवा बह रही है, इसी हवा, इसी मौसम में खेत–खलिहान, बाग–बगान से लेकर जीवन का हर हिस्सा आनंदित हो रहा है। वाकई, हम जिस तरफ देखें तो फूलों की बहार है, हर जीव वसंत ऋतु के स्वागत में खड़ा है। ये वसंत महामारी की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते भारत के लिए नई उम्मीद, नई उमंग लेकर आया है। इस उल्लास में, भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक, महाराजा सुहेल देव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है।

प्रधानमंत्री ने सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक (एमके–1ए) सौंपा

पीएम ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की,भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेन्नई में अनेक प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक (एमके–1ए) भी सौंपा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं नवाचार और स्वदेशी विकास की प्रतीक हैं। इन परियोजनाओं से तमिलनाडु की प्रगति को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि तंजावुर और पुदुक्कोट्टई को विशेष रूप से लाभ मिलेगा क्योंकि यहां आज 636 किलोमीटर लंबी ग्रैंड एनीकट कैनाल प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना से व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। इससे 2.27 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी। प्रधानमंत्री ने खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन और जल संसाधनों के उचित उपयोग के लिए तमिलनाडु के किसानों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ग्रैंड एनीकट हमारे गौरवशाली अतीत का एक जीवंत प्रमाण है। यह हमारे राष्ट्र के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के लिए भी एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने तमिल कवि अव्वायर का हवाला देते हुए जल संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि यह केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक विषय भी है। उन्होंने 'प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रोप मोर क्रोप)' के मंत्र को याद रखने की जरूरत पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के जिस नौ किलोमीटर लम्बे हिस्से का उद्घाटन किया उसके बारे में उन्होंने बताया कि यह परियोजना कोविड महामारी के बावजूद निर्धारित समय में पूरी हो गई है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के अनुरूप है। इस परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉहक स्थामनीय रूप से खरीदे गए हैं और निर्माण गतिविधियां भारतीय ठेकेदारों ने पूरी की है। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेरख किया कि इस वर्ष के बजट में इस परियोजना के दूसरे चरण के 119 किलोमीटर निर्माण के लिए 63 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है।

तमिलनाडु में परियोजनाओं का उद्‌घाटन

यह एक बार में किसी भी शहर के लिए स्वीकृत की गई सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि शहरी परिवहन पर उचित ध्यान देने से यहां नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से सुविधा उपलब्ध होती है। इससे व्यापार में भी मदद मिलती है। चेन्नई बीच, गोल्डसन क्वाड्रीलैटरल का इन्नोर अट्टीपट्टू खंड एक उच्च यातायात घनत्व वाला मार्ग है। चेन्नई बंदरगाह और कामराजार बंदरगाह के बीच तेजी से माल की ढुलाई सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है उन्हों ने यह विश्वास जताया कि चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के बीच चौथी लाइन इस संबंध में मदद करेगी।

के महाकवि सुब्रमण्यम भारती के लेखन से प्रेरित है। उन्होंने कहा आइए हम हथियार बनाएं, आइए हम कागज बनाएं, आइए हम कारखाने बनाएं, आइए हम स्कूल बनाएं, आइए हम वाहन बनाएं, जो आगे बढ़ सकें और उड़ सकें। आइए हम जहाज बनाएं जो दुनिया को हिला सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि दो में से एक रक्षा गलियारा तमिलनाडु में है। इस कॉरिडोर को पहले ही 8100 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो गई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु पहले से ही भारत का एक प्रमुख ऑटो मोबाइल विनिर्माण केन्द्रं है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को भारत के टैंक विनिर्माण केंद्र के रूप में

उन्होंने यह भी बताया कि वेल्लुपुरम तंजावुर तिरुवरुर परियोजना का विद्युतीकरण डेल्टा् जिलों के लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले की बरसी पर इस हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्हें हमने इस हमले में खो दिया था। हमें अपने सुरक्षा बलों पर बहुत गर्व है। उनकी बहादुरी से आने वाली पीढियों को प्रेरणा मिलती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू किये हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल

विकसित होते देखा है। एमबीटी अर्जुन मार्क–1ए के बारे में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मैं स्वदेशी रूप से डिजाइन और विनिर्मित यह टैंक सेना को सौंपते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूं। यह टैंक स्वदेशी गोला–बारूद भी उपयोग करता है। तमिलनाडु में बना हुआ टैंक देश की सुरक्षा के लिए उत्तरी सीमाओं में उपयोग किया जाएगा। यह भारत की एक जुट भावना– भारत के एकता दर्शन को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिए जाने से यह क्षेत्र पूरी गति से आगे बढ़ेगा। हमारे सशस्त्र बल भारत के साहस के प्रतीक हैं। इन्होंने समय–समय पर यह दर्शाया है।

खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों को सरकार का पूरा समर्थन है : प्रधानमंत्री

भारत सरकार केरल में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अनेक प्रयास कर रही है : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोच्चि, केरल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल, केरल के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया, श्री वी. मुरलीधरनउपस्थित थे।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्घाटन किए गए कार्यों में विविध क्षेत्र शामिल हैं। वे भारत के विकास पथ को ऊर्जा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि आज शुरू होने वाली प्रोपीलीन डेरिवैटिव पेट्रोकेमिकल परियोजना (पीडीपीपी) से भारत की आत्मानिर्भर होने की यात्रा में मदद मिलेगी क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला हासिल होगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसी तरह, रो–रो वेसल्स के साथ, जलमार्ग के रास्ते सड़क की लगभग तीस किलोमीटर की दूरी 3.5किलोमीटर हो जाएगी जिससे भीड़–भाड़ कम होने और अधिक सुविधा मिलने के साथ, वाणिज्य और क्षमता–निर्माण में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार केरल में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अनेक प्रयास कर रही है। कोच्चि में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल,सागरिका का उद्घाटन इसका एक उदाहरण है। सागरिका क्रूज टर्मिनल समुद्री पर्यटन करने वाले एक लाख से अधिक पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करेगा। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर महामारी संबंधी प्रतिबंधों के

कोच्चि, केरल में परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास

कारण स्थानीय पर्यटन में वृद्धि की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय पर्यटन उद्योग में उन लोगों के लिए आजीविका और हमारी संस्कृति व हमारे युवाओं के बीच संबंध को गहरा करने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने नवीन पर्यटन संबंधी उत्पादों के बारे में सोचने के लिए स्टार्ट–अप का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में अच्छी तरह से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यटन सूचकांक रैंकिंग में, भारत पैंसठ से चौंतीसवें स्थान पर आ गया है।

प्रधामंत्री ने कहा कि क्षमता निर्माण और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय विकास के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। आज 'विज्ञान सागर' के विकास कार्य और साउथ कोल बर्थ का पुनर्निर्माण इन दोनों कारकों में योगदान देगा। कोचीन शिपयार्ड का नया ज्ञान परिसर विज्ञान सागर विशेष रूप से समुद्री इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के इच्छुक लोगों की मदद करेगा। साउथ कोल बर्थ रसद लागत में कमी लाएगा और कार्गो क्षमता में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज, बुनियादी ढांचे की परिभाषा और दायरा बदल गया है। यह केवल अच्छी सड़कोंय कुछ शहरी केंद्रों के बीच विकास कार्य और कनेक्टिविटी से आगे चला गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिये बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए 110 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्थो के विकास के लिए देश की योजना को रेखांकित करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में हमारी परिकल्पजना और कार्य शामिल हैं। अधिक बंदरगाह, वर्तमान बंदरगाहों में बुनियादी ढांचे में सुधार, एफएफ–समुद्र तट की ऊर्जा, स्थायी तटीय विकास और तटीय कनेक्टिविटीष। प्रधानमंत्री मत्यंस सम्पदा योजना के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मछुआरा समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें और अधिक क्रेडिट सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, भारत को एक समुद्री– खाद्य निर्यात का केन्द्र बनाने के लिए काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट महत्वपूर्ण संसाधनों और योजनाओं को समर्पित है जिससे केरल को लाभ होगा। इसमें कोच्चि मेट्रो के अगले चरण को शामिल किया गया है।

कोरोना चुनौती के लिए भारत की उत्साही प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से खाड़ी में भारतीय प्रवासियों की मदद करने के लिए सरकार के प्रयास को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत को खाड़ी में अपने प्रवासी भारतीयों पर गर्व है। वंदे भारत मिशन के तहत, पचास लाख से अधिक भारतीय घर वापस आए। उनमें से कई केरल से थे। प्रधानमंत्री ने वहां की जेलों में बंद अनेक भारतीयों को रिहा कराने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के प्रति विभिन्न खाड़ी देशों द्वारा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। "खाड़ी देशों ने मेरी व्यक्तिगत अपील का जवाब दिया और हमारे समुदाय का विशेष ध्यान रखा। वे क्षेत्र में भारतीयों की वापसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने उस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सीधी उड़ान की व्यववस्थाम की है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों को पता होना चाहिए कि उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार का उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है।"

उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा : अमित शाह

जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा मत बनाइए, राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यह देश का संवेदनशील हिस्सा है: केन्द्रीय गृह मंत्री

Amit Shah, Minister, Home Affairs

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू –कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब दिया। श्री शाह ने कहा कि कई सांसदों का मानना है कि इस विधेयक को लाने का मतलब है कि जम्मू–कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों से फिर वायदा करते हैं कि राज्य का विकास जो रूक गया था उसके पटरी पर आने के बाद उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा। उन्होने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यह देश का संवेदनशील हिस्सा है। उनको कई बार घाव लगे हैं, उनके मन में शंकाएं पड़ी हैं जिन पर मरहम लगाना इस सदन का काम है। श्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर हमारे दिल में है। नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों,कानूनों और योजनाओं से नहीं चलती बल्कि भावना से चलती है और हम मानते हैं जम्मू कश्मीर हमारा है,आप हमारे हो,पूरा देश आपका है और पूरा देश आपके साथ खड़ा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक कोर्ट में है और सर्वोच्च अदालत 5 जजों की बेंच बनाई है,आवश्यकता पड़ने पर सरकार अपना पक्ष रखेगी किंतु इसके कारण सरकार वहां का विकास रोक दे यह उचित नहीं है। उन्होने कहा कि अरुणाचल, गोवा और मिजोरम भी राज्य हैं और जहां विशेष प्रकार की भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थिति होती है वहां राज्य के विकास के लिए अधिकारी भेजने पडते हैं। श्री शाह ने एक सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि धर्म के आधार पर सरकारी अधिकारियों की संख्या को बांटना उचित नहीं है। श्री शाह ने कहा कि देश भर के अन्य राज्यों में भी आइएएस और आइपीएस अधिकारी है उनसे इन राज्यों के लोकल अधिकारियों का अधिकार नहीं जाता तो जम्मू कश्मीर में कैसे जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का अफसर नहीं है सभी देश के अधिकारी हैं। कश्मीर के युवा को भी देश के ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार है।

श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के फैसले देश की संसद करती है और कोई बाहरी किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। अफवाहों को रोकने के लिए समय की आवश्यकता थी इसलिए 4ळ से 2ळ किया गया। उन्होंने कहा कि सुख, शांति और सलामती से रहना हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। श्री अमित शाह ने कहा कि 370 और 35ए टेंम्परेरी एग्रीमेंट (temporary agreement)था लेकिन इसे सालों तक चलाया गया। । मोदी सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती बल्कि देश हित में फैसले करती है। श्री शाह ने कहा कि देश की जनता को 1950 से वादा था कि देश में दो विधान,दो निशान

और दो संविधान नहीं रहेंगे और मोदी सरकार ने उसको पूरा किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सबसे पहला काम पंचायती राज की पुर्नस्थापना की है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित, गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे जिसे अब साकार किया गया है। श्री शाह ने सदन को बताया कि जिला पंचायत के चुनाव में 51.7 प्रतिशत वोटिंग हुई और कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी, चुनाव में घपला और अशांति नहीं हुई और भयरहित होकर लोगों ने मतदान किया। श्री शाह ने कहा कि जिन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया उनका साथ कश्मीर की जनता ने भी छोड़ दिया। श्री शाह ने कहा कि वे सफल चुनावों के लिए वहां की जनता, सुरक्षाबलों और चुनाव आयोग को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी उसको सब ने मिलकर पूरा किया है। श्री शाह ने कहा कि कुल 4483 सरपंच निर्वाचन क्षेत्रों में से, 3650 सरपंच निर्वाचित हुए और 35029 पंच निर्वाचन क्षेत्रों में से, 23660 पंच निर्वाचित हुए। 3395 पंचायतों का विधिवत गठन हुआ और 1088 प्रशासक नियुक्त किए गए। विगत महीनों में पंचायतों को सुदृढ़ किया गया है और 21 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं। साथ ही पंद्रह सौ करोड़ रुपए उनके खाते में डाल कर उन्हें मजबूत किया गया जिनमें आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, मनरेगा की मॉनीटरिंग और खनन का अधिकार संबंधी विषय शामिल हैं। इससे वह आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास करेंगे और यह सब धारा 370 हटने के कारण संभव हो सका है। 01 जून 2020–21 से, सरपंचों ने मनरेगा योजना के लिए भुगतान शुरू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इस वर्ष और लगभग 1000 करोड़ रुपए सौंपे जाएंगे। हाल के एक अन्य निर्णय में जम्मू और कश्मीर सरकार ने खनन अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को सौंप दिए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय और अग्रता सूची में औपचारिक स्थान प्रदान किया गया। बीडीसी अध्यक्ष को डीएम के समान स्थान दिया गया।पंच–सरपंच की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। सभी राज्य पदाधिकारियों को आवंटित पंचायतों के अंदर दो दिन, एक रात का प्रवास करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

श्री शाह ने का कि इन लोगों को वहां के अटके हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए, पंचायतों का सशक्तिकरण करने का कार्य दिया गया है। लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 20,000 विकास परियोजनाओं की पहचान की गयी। अब तक तीन बार यह कार्यक्रम चलाया जा चुका है। पूरे जन अभियान और ब्लॉक दिवस के दौरान, पाँच लाख से अधिक प्रमाण पत्र जिनमें अधिवास, जन्म और मृत्यु तथा दिव्यांका शामिल हैं जारी किए गए हैं। लगभग 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवर किया गया है। रोजगार कार्यक्रम के तहत 10,000 युवाओं को कवर किया गया, लगभग 6,000 कार्य शुरू किए गए हैं, युवाओं के बीच 4,400 खेल किट वितरित किए गए। प्रत्येक बुधवार को ब्लॉक दिवस आयोजित किया जाता है जिसे अब स्थायी संस्थागत रूप दिया गया है और इसे संघ राज्य क्षेत्र में 82 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। गाँव की ओर वापस चलें की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए भागीदारी कार्यक्रम दृ संघ राज्य क्षेत्र के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 6 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

श्री अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जम्मू– कश्मीर उच्चतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, उसे कुछ शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री का विकास पैकेज पीएम द्वारा घोषित एक मेगा विकास और पुनर्निर्माण पैकेज है। इसमें जम्मू कश्मीर के लिये 58627 करोड़ रुपये के परिव्यय की 54 परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित पीएमडीपी योजना में जून 2018 में व्यय 26 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2020 में 54 प्रतिशत हो गया। इनमें से 20 परियोजनाएँ, जिनमें 7 केंद्रीय क्षेत्र और 13 संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएँ शामिल हैं या तो पूर्ण हो गई हैं या काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। इस वित्त वर्ष के अंत तक 8 और परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो गया है 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को शीघ्र खोला जाएगा। चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। विश्वस्तरीय, सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए श्रीनगर और जम्मू शहरों के लिए एलिवेटेड लाइट रेल प्रणाली की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के लिए 10,599 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार किया गया है। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम (एलआरटीएस) जिसमें जम्मू में एक कोरिडोर और श्रीनगर में दो कोरिडोर होंगे, 4 वर्ष में पूरा हो

जाएगा। परियोजना के डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है और मूल्यांकन और वित्तपोषण के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में हाइड्रोपावर की बहुत बड़ी संभावना है। उन्होने कहा कि हम आपकी तरह जम्मू कश्मीर को मंथर गति से नहीं चलाना चाहते बल्कि वहां के विकास को द्रुत गति से चलाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के पास प्रचुर जल संसाधन हैं। 14867 मेगावाट की कुल ज्ञात विद्युत क्षमता में से, पिछले 70 वर्षों में केवल 3504.90 मेगावाट का दोहन किया जा सका है। यूटी ने अब 2025 तक लगभग 3498 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता तैयार करने की योजना बनाई है। पिछले 2 वर्षों में ही लगभग 3000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को फिर से शुरू किया गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर में शत प्रतिशत लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 3,57,405 लोगों को 70 साल से बिजली नहीं मिल रही थी उन्हें 17 महीने में बिजली दी गई है। इस वर्ष 36 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाकर एलओसी पर स्थित करन और मुन्दिआन गांवों को ग्रिड से जोड़ दिया गया। सितम्बर 2022 तक सभी 18.16 लाख ग्रामीण परिवार पाइप द्वारा 100 फीसदी जलापूर्ति से कवर हो जाएँगे। दो जिलों में शत–प्रतिशत घर कवर हो गए हैं। मार्च 2021 तक दो और जिले में शत–प्रतिशत घर कवर हो जाएंगे। मार्च 2022 तक नौ जिले कवर हो जाएंगे और बाकी सात जिले सितम्बर 2022 तक कवर हो जाएँगे। श्री शाह ने कहा कि'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (पीएमजीएसवाई) के तहत जम्मू और कश्मीर 2020–21 में 5300 कि.मी. सडकों का निर्माण होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 17 महीनों में स्वास्थ्य संबंधी कई परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है और शेष पर काम किया जा रहा है। पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से कुल 881.17 करोड़ रुपए की पूरी राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 754.13 करोड़ रुपए की राशि अब तक व्यय की जा चुकी है। पीएमडीपी के तहत 140 चालू नई स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू की गयी हैं, 75 परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं, 26 के वर्तमान वित्त वर्ष 2020–21 में और बाकी 39 के 2021–22 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है। इनमें श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया बाल अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाले नए मातृत्व अस्पताल, जम्मू में नए हड्डी और जोड़ अस्पताल, जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लाक, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण, जीएमसी श्रीनगर में नर्सिंग महाविद्यालय का निर्माण, 17 जिला अस्पतालों का निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि एबी–पीएमजेएवाई– सेहत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को पाँच लाख रुपये तक निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य बीमा को समावेशी बनाने के लिए सरकार ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना की परिकल्पना की है। यह कवरेज इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को प्रदान किया गया है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। पीएम–जेएवाई का परिचालन विस्तार एबी–पीएमजेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए 5.97 लाख परिवारों के अलावा लगभग 15 लाख अतिरिक्त परिवारों तक किया गया है और यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना के तहत अब तक 20.02 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 1.91 लाख लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक लगभग 41 फीसदी परिवारों, जिनमें कम से कम एक सदस्य पंजीकृत है, का सत्यापन किया जा चुका है। पीएम–जेएवाई योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इस योजना के तहत भी सेवाएं प्रदान करेंगे। श्री शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एलजी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ा गया और टीकाकरण भी किया जा रहा है। 17 महीने में 7 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें लगभग 1100 बच्चे जम्मू–कश्मीर के डॉक्टर बन कर स्वास्थ्य सेवा में आगे आएंगे। भारत सरकार द्वारा पंद्रह बीएससी नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई है जिनमें 5 नए नर्सिंग कॉलेज और 10 मौजूदा एएनएम जीएनएम स्कूलों का उन्नयन शामिल है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अलग–अलग लगभग 115 योजनाएं देश के दलित, गरीब, पिछडे, आदिवासियों के लिए बनाई थी जो वहां पर लागू नहीं थी किंतु राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। घर घर बिजली देने, गैस सिलेंडर देने सहित स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर 100ः ओडीएफ हो गया है।

युवाओं के लिये नया सवेरा है अभ्युदय योजना : योगी आदित्यनाथ

UPSC और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, 18 मंडलों में सेंटर का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश के गरीब मेधावी बच्चों को अब IAS-IPS बनने के लिए कोचिंग सेंटर्स की भारी–भरकम फीस नहीं देनी होगी।प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 फरवरी सोमवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 18 मंडलों में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। जहां वसंत पंचमी यानी मंगलवार से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। यह कक्षाएं फिजिकल व वर्चुअल दोनों प्रारूपों में चलाई जा रही हैं। अभी तक प्रदेश के 50 हजार छात्रों ने कोचिंग में पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

मुख्यमंत्री का संबोधन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने कोरोनकाल में कोटा में फंसे प्रतियोगी छात्रों व उनके अभिभावकों की छटपटाहट देखी थी। छात्रों को वापस लाने के लिए राजस्थान की सरकार ने

हमें बसें नहीं दी थी। मैं उनकी पीड़ा नहीं देख सका था। इसलिए मैंने यहां अधिकारियों से कहा कि उनके लिए परिवहन निगम की बसें भेजें। अभ्युदय योजना में प्रदेश में कल मंगलवार से कक्षाएं शुरू होंगी। जिन युवाओं का संक्षिप्त टेस्ट से सेलेक्शन हुआ है, उन्हें मंडल मुख्यालय में क्लास अटेंड करने का अवसर मिलेगा। हमारा प्रयास होगा कि एक करोड़ बच्चे एक समय में एक क्लास से जुड़ सकें।

ये एक अभ्युदय योजना सिर्फ कोचिंग निर्माण नहीं है। ये एक नींव निर्माण की भी प्रक्रिया है। हमारा प्रयास है कि उत्कृष्ट फैकेल्टी को इससे जोड़ेंगे और नवीनतम परीक्षाओं को भी जोड़ेंगे। हम मस्तिष्क को सदैव खुला रखें, ज्ञान को प्राप्त करने लिए हमेशा व्यापक सोचें। **IIT&JEE**, **NEET** जैसी परीक्षाओं के लिए जिसको जानकारी लेनी है, ये अभ्युदय उसका मंच बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले चै परीक्षा के आंदोलन के बारे में किसी से छिपा नहीं है। अब पारदर्शिता से परिणाम आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि हम अपने प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ सार्थक और नया करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रदेश युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत हारे बिना अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है। सरकार आपकी प्रतिभा को एक मंच देने का ही कार्य नहीं करेगी बल्कि एक योग्य योजक के रूप में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण देश और दुनिया की जो सबसे अच्छी फैकेल्टी होगी उसे आपके साथ जोड़कर आपके मार्गदर्शन के लिए ततपरता के साथ कार्य करेगी।

अभ्युदय योजना के लिए कोचिंग पाने वाले छात्रों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जा रहा है। छात्रों को वेबसाइट **abhyuday-up-gov-in** पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वेबसाइट पर जाने पर 8 तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले कैंडिडेट्स को कार्यरत आईएएस, आईपीएस भारतीय वन सेवा, पीसीएस, पीपीएस सहित अन्य अधिकारियों के जरिए मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा रिटायर्ड अधिकारी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी, विभिन्न विषयों के संस्थानों, कॉलेजों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का पैनल एक बनाया जाएगा।

इस योजना के तहत UPSC-UPPSC समेत अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं SIs JEE NEET **NDACDS, SSC TET** अर्धसैनिक, केंद्रीय पुलिस बल, बैंकिंग, बीएड समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कराई जाएगी। इतना ही नहीं संघ लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं और इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। योजना के बेहतर क्रियान्वन के लिए 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है।

योजना के तहत सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को तीन पार्ट में मदद मिलेगी। पहले रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा के जरिए चयनित हुए कैंडिडेट्स को क्लास रूम में पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी। दूसरा प्रतिभागी ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर पाएंगे और तीसरे पार्ट के तहत स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल सेंटर्स से उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए इस योजना शुरुआत की गई है।

इस अभिनव कोचिंग में ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल और लेक्चर आदि तो उपलब्ध होंगे ही ऑफलाइन क्लास (भौतिक कक्षाओं) में IAS और PCS परीक्षा के लिए प्रशिक्षु IAS IPS IFS (वन सेवा), PCS अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। जबकि NDA और CDS की परीक्षा के लिए प्राचार्य, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल द्वारा गाइडेंस मिलेगी। NEET और JEE के लिए अलग कक्षाएं चलेंगी। अधिकारियों के अलावा विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी अतिथि व्याख्याता के तौर पर आमंत्रित किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश : 5.50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश बजट 2021-2022

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को पांचवा बजट पेश किया पिछले वित्तीय वर्ष से इस वर्ष 38 हजार 740 करोड़ रुपये ज्यादा 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख का ऐतिहासिक बजट पेश वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में और एक कदम

बजट विशेष

- स्वास्थ्य के लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था
- कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
- महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
- गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
- प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये
- मेडिकल कालेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
- जन आरोग्य् योजना के लिए 142 करोड़ रुपये

पंचम प्राथमिकताएं

खेती किसानी पर ध्यान : आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना से लेकर दुर्घटना कल्याण योजना तक सरकार का विशेष अभियान स्पष्ट

सब पढ़े-सब बढ़े : प्रत्येक मंडल पर विश्वविद्यालय, गुरुकुल छात्रों को निःशुल्क शिक्षा छात्रावास और भोजन

ढांचागत विकास : 11048 करोड़ रुपये गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस व के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आगे बढ़ी सरकार

रोजगार का अधिकार : एक्सप्रेस वे के किनारे आईटी हब से लेकर रक्षा उत्पादों के केन्द्र स्थापित होंगे। प्रदेश के वस्त्र उद्योग के लिए भी नीति तय

गांव की प्रगति पर फोकस : हर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना से गांवों की अर्थव्यवस्था पर सरकार का फोकस। ओडीओपी को उद्योग हब बनाने पर संकल्पित

उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर विशेष (आगे के पृष्ठों पर)

समावेशी बजट

प्रस्तुत बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रूपये)
बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित

यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है।
हवा की ओट लेकर चिराग जलता है।।

इन पंक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार 22 फरवरी को विधानसभा में सर्वसमावेशी 5वां पूर्ण बजट 2021–22 पेश किया। एक नया रिकार्ड रचते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारित बजट में प्रदेश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, वकीलों, सहित हर किसी का ध्यान रखा गया। आम सरकारों की तरह चुनावी बजट न होकर यह पूर्ण समावेशी बजट था। इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का है। जबकि 2020–21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था। इस साल बजट 38 हजार 740 करोड़ रुपए ज्यादा है। योगी सरकार का यह बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2020 चुनौतियों से भरा रहा। बावजूद इसके सरकार ने अच्छे काम को आगे बढ़ाया।

चुनाव में जाने से पहले के अपने इस बजट में योगी सरकार ने किसानों को फिर से आगे रखने का पूरा प्रयास किया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी और सस्ते लोन की व्यवस्था की गई है। वहीं, महिलाओं के लिए दो नई योजनाओं को लांच किया गया। एक्सप्रेस–वे और एयरपोर्ट का नेटवर्क बिछाने पर भी फोकस किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के हितों के लिए तीन योजनाओं को आरंभ किया जा रहा है। कुल मिलाकर भाजपा सरकार ने प्रदेश के ढांचागत विकास योजनाओं पर फोकस रखा है जिससे युवाओं को बडे स्तर पर रोजगार मिलने की राह प्रबल होगी।

27 हजार करोड़ की नई योजनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रुपए) की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। सदन में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2021–22 बजट में प्रदेश के

युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ–साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं और त्वरित न्याय देना हमारी प्राथमिकता रही है। सरकार ने 54 लाख को भरण पोषण भत्ता दिया। 29.58 करोड़ मानव दिवस मनरेगा में सृजित किए गए। बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों पर निजी क्षेत्र की मदद से औद्योगिक पार्क बने। प्रतियोगी छात्रों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है। यूपी में इस साल जनवरी तक 7.02 करोड़ बैंक खाते खुले हैं। अभ्युदय योजना में छात्रों को अब टैबलेट दिया जाएगा।

युवाओं के लिये कई योजनाएं

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र–छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है। अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे।युवाओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

युवा अधिवक्ताओं को सौगात

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई गई है। इसके तहत श्रमिकों को मदद की जाएगी। महिला श्रमिकों को बराबरी की मजदूरी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में 5 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना कर मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया गया हे जिससे महिलाओं और छात्राओं को मिलेगा। रोजगार के लिए जनपदों में काउंसलिंग सेंटर बनाने की योजना है। सामर्थ्य योजना के तहत महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो किसी काम में ट्रेंड हो सकें और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़े।

किस सेक्टर को क्या मिला?

खेती-किसानी-बागवानी

किसान पर रहा ध्यान

- किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का बजट है। किसानों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा होगा जिसमें इस बार बंटाई किसान को भी शामिल किया गया है।
- नये बीमा योजना में इस बार बंटाइदार किसान भी शामिल हैं।
- किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपये की बजट में योजना हैं

- रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना होगी जिससे किसानों को सिंचाई में लाभ होगा।
- पिछले चार वर्षों में सरकार ने गन्ना किसानों के 1.23 लाख रुपए का रिकार्ड भुगतान कराया गया है। दूसरी सरकारों से 27,785 करोड़ रुपए ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान भाजपा सरकार ने किया है।

कृषि- उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित।
- वर्ष 2020–2021 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित।
- वर्ष 2021–2022 में 62 लाख 50 हजार कुन्तल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी स्थापित की जा रही है जो दिसम्बर, 2021 में शुरू होना सम्भावित है। आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल।
- निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर–मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3500 टी.सी.डी. की गई जिसे 5000 टी.सी.डी. तक बढ़ाने का लक्ष्य। इससे लगभग 1,00,000 किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश : 5.50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान–

- कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का निर्णय,जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ। शेष 03 कृषि विज्ञान केन्द्रों को भूमि अधिग्रहित, संचालन की कार्यवाही जल्द आरंभ

गौ आश्रय स्थल बनेंगे

- सभी न्याय पंचायतों में गौ–आश्रय स्थलों के विकास के लिए स्थानीय सहभागिता और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता की सहभागिता कराई जाएगी।
- ब्रीड इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति के तहत पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ–साथ नवीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण होगा।
- गौ–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ अस्थायी गो–आश्रय स्थल स्थापित होंगे। इस पर सरकार 80 करोड़ रुपये व्यय करेगी
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका–मुँहपका रोग से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य है।

मत्स्य पालन से रोजगार

- ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादनध्मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य ।
- 02 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाएगा
- 2021–2022 में नयी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपये की व्यवस्था

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट

महिलाओं का उत्थान

महिलाओं के लिए दो नई योजना का ऐलान

1. कन्या कुपोषण योजना 100 करोड़
2. महिला सार्म्थ्य योजना 1200 करोड़

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और बेहतर कर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की बजट का इंतजाम किया गया है।
- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट का बजट है।
- पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये का बजट है।
- वित्तीय वर्ष 2021–2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये बजट में दिये गये हैं।

युवाओं के लिये बजट

- ''मुख्यमंत्री अभ्युदय'' योजना के अंतर्गत पात्र छात्र–छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे।
- संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना प्रस्तावित।
- युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिये हेतु 8.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की

स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- कोविड–19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- आयुष्मान भारतयोजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढाँचासृजित किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये 54 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के
- मण्डलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश में 13 जनपदों– बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा , ललितपुर, लखीमपुर –खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये व्यय होंगे। 9 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर है।
- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने हेतु 48 करोड़ रुपये का बजट है।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मीरजापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य। इस हेतु 960 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- मा0 अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- लखनऊ में इंस्टीटयूट ऑफ वायरोलॉजी एण्ड इन्फेक्शस डिजीजेज के अन्तर्गत बायो सेफ्टी लेवल–4 लैब की स्थापना का लक्ष्य।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना के अन्तर्गत संजय गांधी पीजीआई, लखनऊ में लेवल–3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जायेगी।

उत्तर प्रदेश : 5.50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था

- एसजीपीजीआई, लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय।
- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 02 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत को सुदृढ़ करने एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य।

जल जीवन मिशन पर ध्यान

जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन हेतु 15,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना हेतु 22 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

स्वच्छता पर रहेगा जोर

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये
- नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये

ढांचागत विकास एवं औद्योगिक विकास

- पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये की बजट दिया गया
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
- गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये
- गंगा एक्सप्रेस–वे निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये दिये गये हैं

प्रदेश की सड़कों का विकास

- वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये

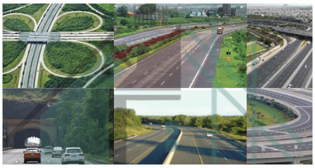

- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपये का बजट दिया गया।
- ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपये व्यय होंगे
- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ0प्र0 मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये मिले
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1192 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये दिये गये जिससे पूर्वांचल का विकास होगा
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें कई योजनाएं शामिल हैं

सिंचाई एवं जल संसाधन

- 2021–2022 में प्रदेश की 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया।

- मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये
- राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये
- सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये
- पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये
- केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उत्तर प्रदेश : 5.50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था

प्रदेश में एयरपोर्ट का जाल

- जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 किया जाएगा। इस परियोजना हेतु 2000करोड़ रुपये दिये गये हैं।
- कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है।
- राज्य में जल्द ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे।
- अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है।
- चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा में सुधार

- बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोब के माध्यम से बिलिंग की जाएगी इससे गुणवत्ता आयेगी।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण।
- वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुये प्रदेशवासियों को निर्वाध विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8262 मेगावॉट उत्पादन क्षमता वृद्धि की परियोजनायें पूर्णता प्रक्रिया में है। जिनको 2020–21 से 2023–24 के मध्य आरम्भ किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य है।
- अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु 140 करोड़ रूपये की व्यय किये जाएंगे।
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये से विकास कार्य होंगें
- दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कोरिडॉर के निर्माण हेतु 1326 करोड़ रूपये
- वाराणसी–गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रूपये
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 478 करोड़ रूपये
- नगरों का विकास 10 स्मार्ट सिटी
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत इस योजना हेतु 10029 करोड़ रूपये व्यय होंगे
- अमृत कार्यक्रम योजना के अर्न्तगत 2200 करोड़ रूपये व्यय करके घरों में बुनियादी सुबिधाएं दी जाएंगी
- प्रदेश के दस शहर–लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयन किये गये। इसके लिए 2000 करोड़ रूपये व्यय होंगे
- स्मार्ट सिटी योजना में चयनित दस नगर निगमों वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के लिये 175 करोड़ रूपये व्यय होंगे
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई।
- शहीदों की स्मृति में पार्क–प्रदर्शनी स्थल–सभागार के निर्माण हेतु 15 करोड़ रूपये व्यय होंगे

स्वच्छ भारत मिशन योजना

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021 – 2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई।
- नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का प्राविधान सरकार ने किया है।

उत्तर प्रदेश : 5.50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था

नियोजन-

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई।
- त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 2500 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई।
- मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

ग्राम्य विकास

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7000 करोड़ रुपये की बजट व्से नये आवास बनेंगे
- मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत 369 करोड़ रुपये से नये आवास बनेंगे
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपये व्यय होंगे
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–3 के बैच–1 के अन्तर्गत 5000 करोड़ रुपये की खर्च होंगे

पंचायती राज-

- ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे प्रदेश के सभी 59000 पंचायतों में भवन बनेंगे
- प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय 10 करोड़ रुपये के व्यय से बनेंगे
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्टग्राम पंचायतों को 25 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता समवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- गाँवों में ई–गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे

सहकारिता- कृषि विकास

- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण देने के लिए ब्याज अनुदान योजना में 400 करोड़ रुपये
- एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

- प्रदेश में एक जनपद – एक – उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पी0पी0पी0 मोड में औद्योगिक पार्क, आस्थान, क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय। इस हेतु 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 30 करोड़ रुपये
- हथकरघा–वस्त्र ,खादी एवं ग्रामोद्योग रोजगार
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण
- सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है
- माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित और संवर्धित करने हेतु 10 करोड़ रूपये व्यय होंगे
- 2021–2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य सरकार ने तय किया है।
- पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था मिलेगी।

आई.टी. सिटी बनेगी

- यमुना एक्सप्रेस–वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना
- बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य।
- लखनऊ एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पी0पी0पी0 मॉडल पर "अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स" बनाया जाएगा जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा

बेसिक-माध्यमिक और उच्च शिक्षा

बेसिक शिक्षा

- कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम देने के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- सभी बच्चों को जूता – मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के छात्र–छात्राओं को स्कूल बैग के लिये 110 करोड़ रुपये व्यय होंगे
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे।
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे

माध्यमिक शिक्षा

- सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में I सुविधाओं के लिये 200 करोड़ रुपए व्यय होंगे
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा
- उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा जिससे संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये
- कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर की क्षमता को दो गुना होगी
- बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा
- एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये व्यय होगें
- निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों को पूर्ण कराने के लिये 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा के स्तर को नई बुलंदी देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा के लिए 200 करोड़ की सौगात दी है। इससे यूपी के हर मंडल में बनेगा एक राज्य विश्वविद्यालय इससे ग्रामीण परिवेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक जिले से दूसरे जिलों व राज्यों में पढ़ाई करने के लिए दौड़ना नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों की सूरत भी बदलने का काम योगी सरकार करने जा रही है।
- प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी। जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा में नामांकन का औसत अच्छा होगा
- राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- चौरी–चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी–चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये खर्च किये जांएगे
- श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये से सड़कों का विकास
- लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे
- शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों को ''उत्तर

प्रदेश गौरव सम्मान'' प्रदान करने का निर्णय जो अब तक पुरस्कारों से वंचित रहे हैं

- इस योजना में प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जायेगी।

पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को आकार

- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपये की
- वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये

प्रदेश में वनीकरण एवं पर्यावरण

- 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य तय।
- 2021 एवं 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित है।
- वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे
- सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे

समाज कल्याण पेंशन योजना

- वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना में 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे
- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति में 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस साल 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे

दिव्यांगजन कल्याण पेंशन

- दिव्यांगजन पेंशन योजना में 10 लाख 87 हजार पात्र दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 720 करोड़ रुपये का खर्च
- कुष्ठ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने हेतु 39 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- दिव्यांगजन दम्पत्ति के बच्चों के पालन–पोषण के लिये पालनहार योजना हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय होंगे
- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना व बचे कार्यो हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ व्यय किये जाएंगे

पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएं

- पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 1375 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे
- अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान में 150 करोड़ रूपये

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं

- अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 829 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे
- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल के लिये संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्स प्लान में 588 करोड़ रुपये व्यय होंगे
- मदरसा आधुनिकीकरण के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट रखा गया है

प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

- जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रूपये व्यय किये जाएंगे।
- उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगणों के आवासीय भवनों के निर्माण पर 100 करोड़ रूपये खर्च होंगे
- उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रूपये तथा इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित

कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई हैं।

परिवहन परिचालन सुदृढ़ता

- बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों का पीपीपी पद्धति पर विकास

श्रमिकों के कल्याण की तीन नई योजना

- विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना ''मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना'' आंरभ हो रही है। इस योजना में 100 करोड़ रुपये खच्र होंगे
- पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिये मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसमें 12 करोड़ रूपये व्यय होंगे
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारम्भ हो रही है। इसमें 100 करोड़ रूपये व्यय किये जाएंगे
- अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये का बजट वदिया गया है जिससे श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोडने में मदद मिलेगी।

प्रपत्र–4
(नियम 8 देखिए)

1.	प्रकाशन का स्थान	:	लखनऊ
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
	राष्ट्रीयता	:	
(क)	क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
(ख)	यदि विदेशी है तो मूल देश	:	XXX
	पता	:	7– विधान सभा मार्ग, लखनऊ
4.	प्रकाशक का नाम	:	प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
	राष्ट्रीयता	:	
(क)	क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
(ख)	यदि विदेशी है तो मूल देश	:	XXX
	पता	:	7– विधान सभा मार्ग, लखनऊ
5.	संपादक का नाम	:	श्री अरुण कान्त त्रिपाठी
	राष्ट्रीयता	:	
(क)	क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
(ख)	यदि विदेशी है तो मूल देश	:	XXX
	पता	:	7– विधान सभा मार्ग, लखनऊ
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हैं, एवं कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज्यादा के साझीदार या शेयरधारक हैं।	:	XXX

मैं प्रो0 श्याम नन्दन सिंह घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

हस्ताक्षर
(श्याम नन्दन सिंह)
प्रकाशक

स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा विकसित करने पर खर्च होंगे 1073 करोड़ रुपये

फ्री कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़, 16 जिलों को मिलेंगे मेडिकल कॉलेज

भाजपा सरकार ने लगभग एक साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेश के मन में फ्री टीकाकरण को लेकर उठ रहे संशय का जवाब दे दिया। बजट आवंटित होने से प्रदेश के मन में एक सकारात्मक संदेश गया। योगी सरकार ने अपने पांचवें बजट में घातक बीमारियों से बचाव, इलाज और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के मद में 12 हजार करोड़ से अधिक व्यय किया जा रहा है। पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 48 करोड़ मिले है। जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की सुविधा के लिए 1073 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य का कुल बजट

चिकित्सा स्वास्थ्य–	10432 करोड़
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण–	8711 करोड़
आयुर्वेद एवं यूनानी–	1366 करोड़
होम्योपैथी–	568. करोड़

स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को 5365 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। खासतौर से प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। गांव स्तर तक जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1073 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस बजट से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जांच की सुविधा का बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सकेगा।

प्रदेश में प्रत्येक नागरिक का हेल्थ आईडी बनाया जाएगा। इस योजना के तहत उनका पूरा डाटा इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड (ईएचआर) के रूप में संरक्षित किया जाएगा। वर्ष 2021–22 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एनडीएचएम) के अंतर्गत यह पूरी व्यवस्था होगी

- अटज बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विवि लखनऊ 100 करोड़
- प्रदेश में शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र के लिए 425 करोड़
- एसजीपीजीआई लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना होगी
- एसजीपीजीआई में वायरोलाजी एंड इंफेक्सियस डिजीज में बीएस–4 लैब
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए 142 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- प्रदेश में असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 480 का व्यय किया जाएगा
- प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के लिए 320 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दिये गये
- लखनऊ, पीलीभीत में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की उत्पादन क्षमता में बढोतरी
- राज्य औषधि प्रणाली के उत्पादन एव उसके नियंत्रण के लिए 54 करोड व्यय होगें
- प्रदेश में मंडल स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों के लिए 77 करोड़ रुपये का व्यय
- प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं के लिए 50 करोड़ अतिरिक्त व्यय होंगे

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एनडीएचएम) शुरू किया जाना है। इसमें व्यक्ति की

सहमति के बाद ही अस्पतालों में डॉक्टर उस व्यक्ति का सम्पूर्ण हेल्थ डाटा इकठ्ठा करके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड के रूप में संरक्षित करेगा। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

16 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था

प्रदेश में इलाज के साथ ही चिकित्सा शिक्षा का ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से 16 जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संतकबीर नगर, शामली और श्रावस्ती में न तो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और न ही निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज। इन जिलों में पीपीपी मोड पर व्यवस्था मेडिकल कॉलेजों का संचालन किया जाएगा।

15 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2125 करोड़

प्रदेश में केंद्र सहायतित योजना के तहत जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके बन रहे 13 मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेजों के लए 175 करोड़ रुपये है। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज को केजीएमयू के सेटलाइट सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है।

महिलाओं का मंगल, कुपोषित बच्चे सेहतमंद

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना शुरू कर रही है। इस योजना के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं एनीमिया ग्रस्त किशोरियों को अतिरिक्त पोषण प्रदान कर सेहतमंद बनाना है। योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ–साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों एवं एनीमिया ग्रस्त 11–14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ एवं राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बच्चों में वजन न बढ़ना,पोषण की कमी, लंबाई ना बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अल्प पोषण जैसी समस्याएं अक्सर देखी जाती है। बच्चों को इन रोगों से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को शुरू कर रही है।

- जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा
- जो किशोरिया एनीमिया से ग्रसित हैं उन्हें योजना का लाभ मिलेगा
- कुपोषित बच्चों तथा किशोरियों को 3 वर्षों तक योजना का लाभ मिलेगा
- 0–वर्ष से लेकर 06 वर्ष तक के बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बदलाव करते हुए उसको पहल से अधिकबेहतरीन तरीके से चलाने पर जोर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का इसके साथ ही पुष्टाहार योजना के लिए 4094 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तुत बजट में महिलाओं के लिए एक नई योजना महिला सामर्थ् योजना की घोषणा की गई है और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दुग्ध उत्पादन और स्वयंसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका में बढोतरी की जाएगी। इस योजना के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को संचालन का अधिकार दिया गया है।

इस बजट में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला सुरक्षा के लिये विशेष अभियान तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी।

नई दिल्ली में आयोजित संगठनात्मक बैठक

हरदोई के बिलग्राम मल्लावां में विधायक श्री आशीष सिंह आशु जी के पिताजी लोकतंत्र सेनानी स्व. श्री शिवनाथ सिंह एवं भाई स्व. आलोक 'नीलू' की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन एवं निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य उपकरण वितरण

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2018-20
फरवरी द्वितीय 2021 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी